वित्तीय वर्ष में फल और सब्जियों की कीमतों में 1991-92 की तदनुरूप अवधि में हुई 12 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में केवल 6 प्रतिशत और दूध में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में गिरावट से, आम आदमी की क्रय शक्ति का अवक्षय नियंत्रित हो गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पूर्ति प्रबंध को सुदृढ़ करके निर्धनों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार की चल रही नीति पहले से मध्यावधि आर्थिक विकास और रोजगार की गति तेज होगी पूर्ति की स्थिति और आय में परिणामी सुधार से आम आदमी को स्थायी लाभ पहुंचने की आशा की जाती है।

ग्रामीण ऋण-माफी योजना हेतु निर्दिष्ट धनराशि

86. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों के दौरान ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत सरकार ने कतिपय धनराशि संवितरित की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का ग्रामीण ऋण माफ किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी और जनवरी, 1993 तक उसमें से केवल 250 करोड़ रुपये संवितरित किये गये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष धनराशि संबंधित संस्थाओं में कब तक संवितरित कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) फरवरी, 93 की स्थिति के अनुसार कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत (ए० आर० डी० और) योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने कुल 7760.96 करोड़ रु० की ऋण राहत प्रदान की है। अब तक भारत सरकार ने बजट प्रावधानों (वर्ष 1990-91) के दौरान 1500 करोड़ रुपए, वर्ष 1991-92 के दौरान 1425 करोड़ रुपए, वर्ष 1992-93 के बजट से 250 करोड़ रुपए) में से 3175 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वर्ष 1992-93 के प्रावधान से शेष 1250 करोड़ रुपए की राशि अभी जारी की जानी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बैंकों से उनके द्वारा दी गई राहत का शत-प्रतिशत सत्यापन करने के और उन पात्र हिताधिकारियों से संबंधित हिस्से को छोड़कर पुनरीक्षित दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बैंकों से अंतिम दावा विवरणों के प्राप्त होने के बाद ही आगे की राशि जारी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण

87. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल-दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई धन राशि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जमा हुई धन-राशि की तुलना में अधिक है जबकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों की धनराशि गत वर्ष की तुलना में कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा लघु उद्योग, अत्यंत छोटे उद्योगों और कृषि क्षेत्र के लिये ऋणों के रूप में अलग-अलग कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन बैंकों द्वारा लघु उद्योग अत्यंत छोटे उद्योगों और कृषि-क्षेत्र को ऋण जारी करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 20 मार्च, 1992 और 25 दिसम्बर, 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियां और बकाया अग्रिम और पूर्व वर्ष 1991 के दौरान तदनुरूप अवधि के लिये समान स्थिति नीचे दी गई है :–

(करोड़ रुपए)

की अन्त की स्थिति के अनुसार	जमाराशियां	ऋण
22 मार्च, 1991	116339	66715
27 दिसम्बर, 1991	125970	67982
वृद्धि	9631 (8.3%)	1267 (1.9%)
20 मार्च, 92	130288	69743
25 दिसम्बर, 92	146813	77607
वृद्धि	16525 (12.7%)	7864 (11.3%)से

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अप्रैल--दिसम्बर, 92 के दौरान जमाराशियों और ऋणों, दोनों के मामले में पूर्व वर्ष 1991 के दौरान तदनुरूप अवधि की तुलना में वृद्धि दर अधिक थी।

(ग) से (च) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित समस्त भारतीय बैंकों को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष कृषि वित्त के लिए अपने कुल ऋण का कम से कम 18% देना अपेक्षित है। अति लघु उद्योग सहित लघु उद्योगों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सितम्बर, 1991 और सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र (प्रत्यक्ष वित्त) और लघु उद्योगों को 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों

की बकाया ऋण की राशि नीचे दी गई है:—

(करोड़ रुपए)

की अन्त की स्थिति के अनुसार	कृषि (प्रत्यक्ष वित्त)	लघु उद्योग (एसएसआई)
सितम्बर, 1991	10464 (15.%)	10400
सितम्बर, 1992	11181 (14.%)	11316

(कोष्ठक के आंकड़े कुल ऋण की तुलना में प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

उक्त से यह देखा जा सकता है कि कृषि और लघु उद्योगों को बकाया राशि में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। प्रतिशतता उपलब्धि के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए 18% के निर्धारित लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त बैंकों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा है।

प्रति व्यक्ति आय में गिरावट

88. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990–91 की तुलना में वर्ष 1991–92 में देश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आयी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990–91 और 1991–92 के लिये देश में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े क्या हैं

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान देश में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है

(घ) क्या यह सच है कि 1990–91, 1991–92 और 1992–93 के वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विदेशी पूंजी के अन्तः प्रवाह में निरंतर वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति आय में निरंतर कमी आने के क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) त्वरित अनुमानों के अनुसार, स्थिर कीमतों (1980–81) पर प्रति व्यक्ति आय (उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद) 1990–91 में 2199 रुपए की तुलना में 1991–92 में 2174 रुपए थी। जिससे 1.1 प्रतिशत की गिरावट का पता चलता है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1990-91 के दौरान 4934 रुपए की तुलना में वर्ष 1991.92 में 5529 रुपए होने का अनुमान है जिससे 12.1 प्रतिशत की वृद्धि जाहिर होती है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ कर 2282 रुपए होने की आशा की जाती है।